राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3,नरेगा)

क्रमांक 4(21) आरडी/नरेगा/एमआईएस/2009–10 जयपुर, दिनांकः– 16/10/09

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2008–09 की सूचनाएँ एमआईएस पर अपलोड करने एवं उन्हें अन्तिम माने जाने के सबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 को समाप्त हुए छः माह व्यतीत हो चुके है। लेकिन फिर भी समस्त सूचनाओं का इन्द्राज अभी तक एमआईएस पर नहीं हुआ है। जिसके कारण योजना के कियान्वयन की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगता है एवं भारत सरकार द्वारा भी इस पर कडा रूख लिया गया है।

दिनांक 15.10.09 को एमआईएस पर उपलब्ध डाटा के अनुसार मुख्य बिन्दुओं की स्थिति निम्नानुसार है :–

1. श्रम मद में भुगतान की स्थिति :– जिलो से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार हुए व्यय एवं एमआईएस पर उपलब्ध व्यय की स्थिति के अनुसार अभी तक कुल 72 प्रतिशत व्यय का इन्द्राज एमआईएस पर किया गया है। झुझुनूं जिले द्वारा जहां सर्वाधिक 88 प्रतिशत व्यय का इन्द्राज किया गया है, वहीं सवाई माधोपुर द्वारा मात्र 43 प्रतिशत व्यय का इन्द्राज किया गया है। जिला डूगरपुर, जालौर, जोधपुर, चूरू, उदयपुर, पाली, बीकानेर, टोंक, झालावाड, बून्दी, चित्तौडगढ, बांसवाडा, जैसलमेर एवं राजसंमद अन्य जिले है जिनमें श्रम मद में व्यय का इन्द्राज राज्य की औसत इन्द्राज से कम है।
2. सामग्री मद में भुगतान :– बडे ही खेद की बात है कि सामग्री मद में मात्र 29 प्रतिशत व्यय का इन्द्राज ही एमआईएस पर किया गया है। जहां सिरोही जिले द्वारा लगभग पूर्ण इन्द्राज किया जा चुका है, टोंक, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, गंगानगर एवं करौली जिले द्वारा नगण्य राशि का इन्द्राज इस मद में किया गया है। सिरोही, बांरा, कोटा, डूगरपुर, बीकानेर एवं नागौर जिले को छोडकर शेष सभी जिलों

में सामग्री मद में इन्द्राज 50 प्रतिशत से भी कम है। यह प्रगतिरत एवं पूर्ण कार्यो पर प्रयुक्त सामग्री के बैंक एण्ड बिलिंग को बढ़ावा देता है। एमआईएस पर सामग्री मद में इन्द्राज नहीं करना शंका उत्पन्न करता है। भीलवाड़ा में सामाजिक अंकेक्षण की प्रकिया में भी यह स्पष्ट हुआ है कि सामग्री मद में बोगस फर्मो से सामग्री क्रय कर घालमेल का प्रयास किया जाता है। निकट भविष्य में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव भी होने वाले है। अतः सामग्री मद में इन्द्राज और भी आवश्यक हो जाता है। कृपया इस सम्बन्ध में विशेष अभियान चलाया जाकर सामग्री मद में हुए व्यय का इन्द्राज तुरन्त प्रभाव से पूर्ण किया जावे।

3. कुल व्यय :– योजना अन्तर्गत गत वर्ष हुए कुल व्यय का 60 प्रतिशत का इन्द्राज ही एमआईएस पर किया गया है। बांरा एवं सिरोही जिले द्वारा ही लगभग 80 प्रतिशत व्यय का इन्द्राज एमआईएस पर किया गया है। राजसंमद, करौली, झालावाड, टोंक, सीकर, बांसवाडा, जालौर, उदयपुर, चित्तौडगढ, सवाईमाधोपुर एवं जैसलमेर जिलों में एमआईएस पर इन्द्राज राज्य के औसत से कम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिलो के पास पिछले वर्ष की राशि अवशेष है।

4. रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या, प्रयुक्त मस्टररोल एवं मानव दिवस सृजन :– प्रगति प्रतिवेदन एवं एमआईएस पर उपलब्ध डाटा के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या एवं प्रयोग में ली गई मस्टररोल की संख्या का इन्द्राज लगभग पूर्ण हो चुका है, परन्तु फिर भी मानव दिवस सृजन का इन्द्राज मात्र 79 प्रतिशत है। इन तीनो मद में उपलब्ध डाटा के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन में इन तीनो मद में दिये गये डाटा में काफी विरोधाभास है। सिरोही एवं जयपुर जिले में तुलनात्मक रूप से अधिक सही डाटा दिये गये है। शेष सभी जिलों में अत्यन्त अंतर पाया गया है। कृपया यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वर्ष 2008–09 में प्रयुक्त की गई सभी मस्टररोल का इन्द्राज एमआईएस पर किया जा चुका है। कुछ मस्टररोल के इन्द्राज की रेण्डम आधार पर जांच भी कराई जाये ताकि यह भी स्पष्ट हो सके कि मस्टररोल का इन्द्राज पूर्ण रूप से किया गया है। उदाहरण के तौर पर चुरु. ने एमपीआर अनुसार 1.05 लाख मस्टररोल उपयोग में ली गई है जबकि एमआईएस में 1.32 लाख एमपीआर फीड़ की गई है। इसके विरुद्व एमआईएस में मानव दिवस सृजन 75 प्रतिशत ही है। इसका अर्थ है कि कहीं त्रुटि हो रही है।

5. 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारो की संख्या :– मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार राज्य मे लगभग 26 लाख परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया, वहीं एमआईएस पर प्राप्त डाटा के अनुसार मात्र 9.45 लाख परिवारों को ही 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जो कि मात्र 36 प्रतिशत है। दौसा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर एवं झालावाड़ जिलों द्वारा एमपीअर में जितने परिवारों के 100 दिवस पूर्ण बताये गये है। एमआईएस में उसकी तुलना में 20 प्रतिशत परिवारों ने भी 100 दिवस पूरे नहीं किये है।

कृपया यह सुनिश्चित किया जावे कि वर्ष 2008–09 में प्रयोग में ली गई समस्त मस्टररोल एवं बिलो का इन्द्राज एमआईएस पर किया जा चुका है। सामग्री मद पर हुए व्यय के इन्द्राज हेतु एक विशेष अभियान चलाया जाकर ग्राम पंचायतों से बिलो की प्रति प्राप्त कर शीघ्र पूरा किया जावे। कृपया अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करले कि दिनांक 31.10.09 तक वर्ष 2008–09 से सम्बन्धित समस्त इन्द्राज एमआईएस पर आवश्यक रूप से हो जाये। दिनांक 31.10.09 के पश्चात एमआईएस पर उपलब्ध डाटा को ही जिले की वर्ष 2008–09 की प्रगति मानी जायेगी एवं इसी के आधार पर उपलब्ध शेष राशि को देखते हुए राशि का आवंटन किया जायेगा। पंचायत समिति में कार्यरत कार्यक्रम अधिकारियों से इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाकर कि वर्ष 2008–09 की समस्त प्रविष्टिया एमआईएस पर दर्ज हो चुकी है, जिले द्वारा इकजाई प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित किया जावे। दिनांक 15.10.09 को एमआईएस एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन का तुलनात्मक विवरण पत्र के साथ संलग्न है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करने का श्रम करे।

भवदीय,

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
3. एमआईएस मैनेजर, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

16/10/09

परियोजना निदेशक, ईजीएस